

# कृषि फोर्स

13 अक्टूबर २०२५



**ASCI**  
Agriculture Skill Council of India

**CEASI**  
CENTRES OF EXCELLENCE FOR  
AGRICULTURE SKILLS IN INDIA



**CEFMI**  
Centre of Excellence for  
Farm Mechanization Skills in India

**CEHSI**  
Centre of Excellence for  
Horticulture Skills in India

[www.ceasi.in](http://www.ceasi.in)



प्रिय पाठकों,  
हमारे साप्ताहिक समाचार पत्र के माध्यम से आप तक पहुँच पाना हमारे लिए एक विशेषाधिकार है। यह समाचार पत्र CEASI की गतिविधियों की धड़कन को दर्शाता है, जो ASCI के संरक्षण में कार्यरत है, और हमारे सामूहिक सफ़र को कौशल विकास एवं सतत कृषि की दिशा में प्रतिबिंबित करता है। यहाँ साझा की जाने वाली हर कहानी हमारी टीमों, साझेदारों और कृषि समुदायों की समर्पित भावना का प्रमाण है। हमारा मिशन स्पष्ट है: किसानों और कृषि-पेशेवरों को वह कौशल, ज्ञान और तकनीक प्रदान करना जिसकी उन्हें बदलते समय में सफल होने के लिए आवश्यकता है। नवाचार और जमीनी स्तर पर जुड़ाव को मिलाकर, हम एक अधिक उत्पादक, लचीले और समावेशी कृषि क्षेत्र की नींव रख रहे हैं।  
मैं आपको आमंत्रित करता हूँ कि आप इस समाचार पत्र को पढ़ें, सीखें और इसमें प्रस्तुत अवसरों में सक्रिय रूप से भाग लें। आपकी सहभागिता ही विचारों को प्रभाव में बदलती है।

## डॉ. सतेंद्र सिंह आर्य मुख्य कार्यकारी अधिकारी



प्रिय पाठकों,  
CEASI का साप्ताहिक समाचार पत्र केवल गतिविधियों का सारांश नहीं है। बल्कि यह एक ऐसा मंच है, जहाँ विचारों का आदान-प्रदान, उपलब्धियों का उत्सव और भारतीय कृषि तथा इसके सहायक क्षेत्रों जैसे डेयरी, बागवानी, कृषि मशीनीकरण, जलवायु लचीलापन आदि के भविष्य के लिए हमारी साझा दृष्टि को और मजबूत किया जाता है। प्रत्येक अंक कृषि क्षेत्र और विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों से नवाचार, सहयोग और प्रगति की कहानियाँ लेकर आता है।

आगे बढ़ते हुए, हमारा ध्यान ज्ञान साझा करने, नवीनतम विकासों को सामने लाने, क्षमता निर्माण करने और सफलता की कहानियाँ हर स्तर पर किसान के खेत से लेकर नीति-निर्माताओं तक पहुँचाने पर रहेगा। ताकि आधुनिक उपकरण, तकनीकें और सर्वोत्तम प्रथाएँ उन तक पहुँच सकें जिन्हें उनकी सबसे अधिक आवश्यकता है। मैं स्वीकार करता हूँ कि यह समाचार पत्र अभी अपने प्रारंभिक चरण में है। मैं पाठकों और हितधारकों से आग्रह करता हूँ कि वे इसमें प्रस्तुत पहलों, प्रशिक्षणों और अद्यतनों से जुड़े रहें, और ऐसी प्रमुख उपलब्धियों व घटनाओं को साझा करें जिन्हें यहाँ प्रकाशित किया जा सके। इसके दायरे, प्रकाशन की आवृत्ति, नए अनुभाग जोड़ने और सुधार के लिए आपके विचार इसे एक आदर्श पत्रिका बनाने में अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे, जो हमें साथ मिलकर और अधिक मजबूत बनने के अवसर प्रदान करेगी।

## जसवंत सिंह कालसी मुख्य परिचालन अधिकारी

### हम कौन हैं:

“सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एग्रीकल्चर स्किल्स इन इंडिया (CEASI)” एक स्वायत्त संस्था है, जो “एग्रीकल्चर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया (ASCI)” के अधीन कार्य कर रही है। यह संस्था कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) के तहत कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में कार्यरत किसानों, मजदूरी श्रमिकों, स्वरोजगार में लगे पेशेवरों, विस्तार कार्यकर्ताओं आदि के लिए कौशल विकास और क्षमता निर्माण का कार्य करती है।

### CEASI कृषि के विभिन्न उप-क्षेत्रों में स्थापित उत्कृष्टता केंद्रों की शीर्ष संस्था है, जैसे कि:

- सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर डेयरी स्किल्स इन इंडिया (CEDSI)
- सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हॉर्टिकल्चर स्किल्स इन इंडिया (CEHSI)
- सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फार्म मेकनाइजेशन स्किल्स इन इंडिया (CEFMI)
- सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर क्लाइमेट रेज़िलिएंट एग्रीकल्चर (CoE-CRA)
- सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एग्रीकल्चर (CoE-AI)

### हम क्या करते हैं:

- **कौशल विकास और क्षमता निर्माण:** कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में हितधारकों की आवश्यकताओं के आधार पर क्षमता निर्माण।
- **ज्ञान प्रबंधन:** वर्कफोर्स मानकों को समर्थन देने हेतु QPs, NOS, स्किल गैप रिपोर्ट और न्यूज़लेटर्स का विकास।
- **अनुसंधान:** उद्योग की मांगों के अनुसार आवश्यकताओं की पहचान और कौशल अंतर को पाटने के लिए अनुसंधान।
- **नीति समर्थन और परामर्श सेवाएं:** नवाचार साझा करने और क्षेत्रीय चुनौतियों को हल करने हेतु नेटवर्क का निर्माण।

### हमारा विज़न

एक स्वायत्त उत्कृष्टता संस्थान जो कृषि में उच्च कौशल युक्त कार्यबल विकसित करने के लिए समर्पित है, नवाचार, तकनीकी प्रगति और सतत प्रथाओं के माध्यम से भारतीय कृषि की समृद्धि और लचीलापन बढ़ाने के लिए कार्यरत है।

### हमारा मिशन

राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर उन्नत कृषि पद्धतियों में कौशल विकास के लिए अग्रणी संगठन के रूप में उभरना, जो सततता, लाभप्रदता, क्षमता निर्माण, ज्ञान प्रसार, नीति समर्थन और नवाचार आधारित अनुसंधान के माध्यम से कृषि क्षेत्र के समग्र विकास को प्रोत्साहित करता है।

### CEASI का प्रभाव:

CEASI भारतीय कृषि में एक परिवर्तनकारी बदलाव ला रहा है, जो व्यक्तियों को सशक्त बनाने, कौशल को निखारने और देशभर में समुदायों को उन्नत करने का कार्य कर रहा है।

- ▶ 15+ राज्य
- ▶ 15 एफपीओ को प्रशिक्षित और सहयोग प्रदान किया गया
- ▶ 20,000 कृषि / डेयरी पेशेवरों को कौशल प्रशिक्षण दिया गया
- ▶ 5000+ उद्यमियों को प्रशिक्षित किया गया
- ▶ 3000+ महिलाओं को सशक्त बनाया गया
- ▶ 30,000+ जीवन को प्रभावित किया गया

## छत्तीसगढ़ में महिलाओं के लिए इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर पायलट का शुभारंभ



छत्तीसगढ़ में रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय (IGKV) के स्वामी विवेकानंद कृषि अभियंत्रण और प्रौद्योगिकी कॉलेज में इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। यह सप्ताह भर चलने वाला कार्यक्रम (6 से 10 अक्टूबर) राज्य परिवहन विभाग के नेतृत्व में महिलाओं के लिए उपयुक्त इलेक्ट्रिक ट्रैक्टरों की कृषि में व्यवहार्यता परखने के लिए आयोजित किया गया है। इस पायलट में CSIR-CMERI द्वारा विकसित CSIR-PRIMA ET 11 ट्रैक्टर शामिल है, जिसे तकनीकी सहायता CSIR-CMERI और ज्ञान सहयोग शाक्ति सस्टेनेबल एनर्जी फाउंडेशन से मिल रहा है।

PRIMA ET 11 छोटे और सीमांत किसानों के लिए बनाया गया

है। इसमें आरामदायक नियंत्रण, कम कंपन, न्यूनतम शोर और सोलर चार्जिंग की सुविधा है। यह ट्रैक्टर खेत में चार घंटे या माल ढोने में छह घंटे तक काम कर सकता है, और इसकी टोइंग क्षमता 1.5 टन तक है। अधिकतम गति 22 किलोमीटर प्रति घंटे है। पायलट के दौरान इसके प्रदर्शन, ऊर्जा दक्षता और छोटे किसानों के लिए इसकी व्यवहारिकता का मूल्यांकन किया जाएगा।

इस पहल का उद्देश्य स्थायी और समावेशी कृषि मशीनरी को बढ़ावा देना और महिला किसानों की आधुनिक कृषि में भागीदारी को प्रोत्साहित करना है। यह पायलट कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के छोटे किसान क्षेत्रों में इलेक्ट्रिक ट्रैक्टरों की संभावित व्यापक अपनाने की दिशा में पहला कदम है। अधिकारियों का लक्ष्य वास्तविक खेती की परिस्थितियों में इसके संचालन, दक्षता और ऊर्जा खपत का आंकलन करना है, ताकि राज्य में पर्यावरण-अनुकूल और तकनीकी कृषि को बढ़ावा दिया जा सके।

## तेलंगाना डिजिटल कृषि में अग्रणी बनने की ओर



तेलंगाना राज्य ने कृषि को लाभकारी, सतत और जलवायु-लचीला बनाने के लिए डिजिटल तकनीक अपनाने की दिशा में कदम बढ़ाया है। उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री डी. श्रीधर बाबू ने कहा कि राज्य में AI, IoT और डेटा-आधारित उन्नत प्रणाली के जरिए छोटे और सीमांत किसानों की उत्पादकता बढ़ाने और लागत घटाने पर ध्यान दिया जा रहा है। राज्य की कुल जनसंख्या का 55 प्रतिशत कृषि से जुड़ा है, और कृषि तेलंगाना की GSDP में महत्वपूर्ण योगदान देती है।

मंत्री ने 'एक्सेलेरेटिंग क्लाइमेट-रेजिलिएंट एग्रीकल्चर इन तेलंगाना' परियोजना की प्रगति की समीक्षा की, जो तीन गांवों

में पिछले दो वर्षों से चल रही है। परियोजना के तहत उन्नत मिट्टी सेंसर, पूर्व चेतावनी प्रणाली और AI-आधारित विश्लेषण प्रणाली के माध्यम से रासायनिक उपयोग और खर्च घटाने का प्रयास किया गया है। उन्होंने जर्मन संस्थान Fraunhofer HHI से कार्यक्रम को पूरे राज्य में फैलाने का आग्रह किया।

बैठक में जर्मनी दूतावास के फूड एंड एग्रीकल्चर विभाग के प्रमुख वोल्कर क्लेइमा, Fraunhofer HHI प्रतिनिधि और राज्य कृषि अधिकारियों ने भाग लिया। इस चर्चा ने यह दिखाया कि तेलंगाना कृषि में अत्याधुनिक तकनीक और स्थायी प्रथाओं को जोड़कर उत्पादकता बढ़ाने, पर्यावरणीय प्रभाव घटाने और छोटे किसानों के वित्तीय सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में काम कर रहा

## ओड़िशा में पायलट एग्री-टेक स्मार्ट फार्म का शुभारंभ



ओड़िशा सरकार ने चार जिलों—कोरापुट के सेमिलीगुड़ा, जाजपुर के सुकिंडा, पुरी के सखीगोपाल और बरगढ़ के चाकुली—में एग्री-टेक स्मार्ट फार्म (ATSF) पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। यह पहल सार्वजनिक-निजी साझेदारी (PPP) मॉडल के तहत 600 हेक्टेयर क्षेत्र में लागू होगी, जिसमें लगभग 66 करोड़ रुपये का निवेश होगा।

सबसे बड़ा साइट सेमिलीगुड़ा (352.58 हेक्टेयर) है, फिर सुकिंडा (200 हेक्टेयर), सखीगोपाल (26.24 हेक्टेयर), और चाकुली (21.6 हेक्टेयर)। इन स्मार्ट फार्मों में माइक्रो-इरीगेशन, IoT सेंसर, ड्रोन, ग्राउंड कैमरा, ग्रीनहाउस और हाइड्रोपोनिक्स जैसी तकनीकें शामिल होंगी। फार्म संचालन में तकनीक

आधारित उत्पादन, प्रदर्शन, पोस्ट-हार्वैस्ट मैनेजमेंट और एग्री-टूरिज्म के मॉड्यूल होंगे।

जिलों को स्थानीय फसलों और जलवायु के अनुसार चुना गया है: सुकिंडा में प्लांटेशन और फ्लोरिकल्चर, सेमिलीगुड़ा में बहु-फसल खेती, सखीगोपाल में विशेष बागवानी जैसे कागजी नींबू और नारियल, और चाकुली में जैविक खेती। पोस्ट-हार्वैस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रोसेसिंग यूनिट, कोल्ड चेन और पैक हाउस शामिल होंगे। निजी भागीदार जैविक खेती, तुलसी, कमल, मैरिगोल्ड, डेयरी, रेशम और प्रॉन फार्मिंग जैसी गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं।

एग्री-टूरिज्म के लिए 25 प्रतिशत जमीन विकसित की जाएगी, जिसमें थीमैटिक कॉटेज, ईको-लॉज, एग्री-ट्रेल, स्मृति दुकान और स्थानीय संस्कृति आधारित रेस्टोरेंट होंगे। इस पहल का लक्ष्य ओड़िशा में तकनीक को कृषि में तेजी से लागू करना और विशेषज्ञता आकर्षित करना है।

## राजस्थान में पीएम धन-धान्य कृषि योजना के तहत किसानों को लाभ



प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली से पीएम धन-धान्य कृषि योजना और पल्स आत्मनिर्भरता मिशन शुरू किया। राजस्थान के आठ जिले—बाड़मेर, जैसलमेर, नागौर, जोधपुर, बीकानेर, पाली, जालोर और चुरू—को देश के 100 कम उत्पादक कृषि जिलों में शामिल किया गया है। चयन में कम फसल घनत्व, सीमित सिंचाई और औसत से कम क्रेडिट सुविधा शामिल है।

मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि योजना का उद्देश्य उत्पादकता बढ़ाना, फसल विविधता को बढ़ावा देना और सिंचाई ढांचा सुधारना है। इसमें कृषि, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन, खाद्य प्रसंस्करण और ग्रामीण विकास विभागों के समन्वय से लागू किया जाएगा। छोटे किसानों को

माइक्रो-सिंचाई सुविधाएं (ड्रिप और स्प्रिंकलर) मिलेंगी, लगभग 23 लाख हेक्टेयर में विस्तार किया जाएगा।

मिट्टी परीक्षण और मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड के आधार पर मशीनरी और इनपुट का उपयोग किया जाएगा। आधुनिक भंडारण सुविधा जैसे गोदाम, कोल्ड स्टोरेज, साइलो और पैकिंग सुविधाएं पंचायत और ब्लॉक स्तर पर स्थापित की जाएंगी। यह कार्यक्रम राजस्थान में प्रौद्योगिकी आधारित, यांत्रिक खेती की दिशा में एक बड़ा कदम है। इसका उद्देश्य उत्पादकता बढ़ाना, श्रम कम करना और जल व संसाधनों के सतत प्रबंधन को सुनिश्चित करना है।

## तेलंगाना में बागवानी क्षेत्र के व्यापक विस्तार की दिशा में कदम



हैदराबाद: तेलंगाना अब अपने बागवानी क्षेत्र के बड़े विस्तार की दिशा में अग्रसर है। वर्तमान में राज्य की मात्र 7% कृषि योग्य भूमि पर ही बागवानी की जाती है, जो दक्षिण के अन्य राज्यों की तुलना में काफी कम है। वर्ष 2023-24 में 11.91 लाख एकड़ भूमि पर बागवानी फसलें उगाई गईं, जिससे 42.58 लाख मीट्रिक टन उत्पादन हुआ। बागवानी क्षेत्र ने राज्य के कृषि सकल मूल्य उत्पादन में लगभग 30% योगदान दिया। प्रमुख फसलें आम, मीठा संतरा, अमरूद, अनार, टमाटर, बैंगन, मिर्च, ताड़ तेल और हल्दी हैं, जो इस क्षेत्र के बढ़ते आर्थिक महत्व को दर्शाती हैं।

हालांकि, राज्य के फल क्षेत्र में आम और मीठा संतरा लगभग

87% हिस्सेदारी रखते हैं, जिससे फसल विविधीकरण की आवश्यकता महसूस की जा रही है। सब्जी क्षेत्र में पिछले दशक में थोड़ी गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन हॉर्टिकल्चर परिप्रेक्ष्य योजना 2035 के तहत बागवानी क्षेत्र का धीरे-धीरे विस्तार और किसानों का उच्च-मूल्य फसलों जैसे ताड़ तेल की ओर रुझान देखा जा रहा है। यह परिवर्तन तेलंगाना की कृषि अर्थव्यवस्था को अधिक विविध और मूल्य-आधारित दिशा में ले जा रहा है।

## गुजरात के उत्कृष्टता केंद्र से बागवानी में नई गति



गांधीनगर: मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर (MIDH) के तहत गुजरात में स्थापित उत्कृष्टता केंद्र (CoEs) बागवानी क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। देशभर में स्वीकृत 58 उत्कृष्टता केंद्रों में से गुजरात में चार केंद्र फलों और सब्जियों के लिए समर्पित हैं। इन केंद्रों की स्थापना इज़राइल, नीदरलैंड और न्यूज़ीलैंड जैसे देशों के सहयोग से की गई है तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद सहित राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थानों से तकनीकी सहायता प्राप्त है।

सबarkantha जिले के वडराड स्थित "संरक्षित खेती और प्रिसिजन फार्मिंग उत्कृष्टता केंद्र" ने अब तक 1.4 करोड़ से अधिक उच्च गुणवत्ता वाली सब्जी पौध तैयार की है और हर

वर्ष उन्नत खेती तकनीकों पर 18 प्रदर्शन आयोजित करता है। प्रशिक्षण और exposure कार्यक्रमों से अब तक 1.13 लाख से अधिक किसान और अधिकारी लाभान्वित हुए हैं। इसी तरह, मेहसाणा जिले के विसनगर में स्थित "सब्जी एवं साइटस उत्कृष्टता केंद्र" में आधुनिक संरक्षित खेती सुविधाएँ उपलब्ध हैं, जो क्षेत्र में वैज्ञानिक और जलवायु-लचीली बागवानी को बढ़ावा दे रही हैं।

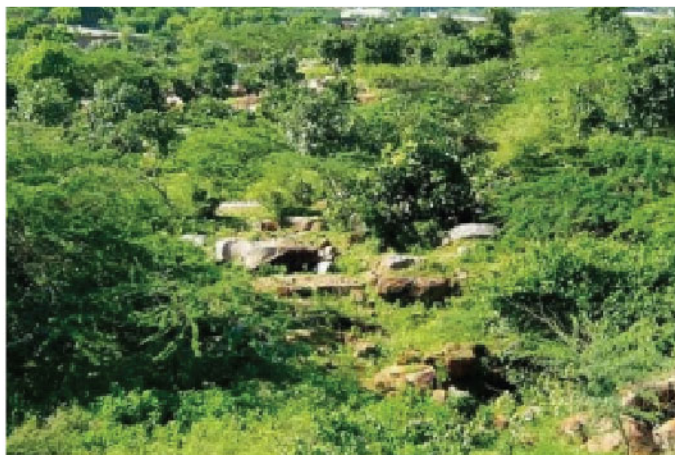
## मध्य प्रदेश में ग्रीन रिवॉल्यूशन 2.0: प्राकृतिक खेती और ग्रामीण कृषि उद्यमों पर जोर



भोपाल: मध्य प्रदेश ने प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ावा देने, बागवानी को सुदृढ़ करने और ग्रामीण युवाओं को कृषि उद्यमिता के माध्यम से सशक्त बनाने के लिए व्यापक रोडमैप जारी किया है। यह पहल राज्य की कृषि परिदृश्य को सतत प्रथाओं, नवाचार और बाजार-उन्मुख दृष्टिकोण के माध्यम से बदलने का लक्ष्य रखती है। प्रत्येक जिले में किसानों की पहचान कर उन्हें तकनीकी मार्गदर्शन और निगरानी सहायता के साथ प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए समर्थन दिया जाएगा, जबकि स्थानीय हाट बाजार और साप्ताहिक बाजार जैविक उत्पादों को बढ़ावा देंगे और बेहतर बाजार कनेक्टिविटी सुनिश्चित करेंगे।

राज्य में केला, टमाटर, संतरा और गुलाब जैसी बागवानी फसलों को बढ़ावा देने के लिए प्रसंस्करण और विपणन नेटवर्क विकसित किए जाएंगे। इसके साथ ही, डेयरी, मत्स्यपालन और जलवायु-सहिष्णु फसलों में युवा-उद्यमिता पर जोर दिया गया है। फसल अवशेष प्रबंधन और पराली जलाने को रोकने के लिए वैज्ञानिक उपाय अपनाए जाएंगे। कृषि, बागवानी, पशुपालन और सहकारी विभागों के समन्वित प्रयासों से मध्य प्रदेश एक स्थायी और लचीली ग्रामीण अर्थव्यवस्था का निर्माण करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

## दिल्ली में 195 एकड़ में फैले 17 नए जंगल स्थापित होंगे



दिल्ली में लगभग 195 एकड़ क्षेत्र में 17 नए जंगल स्थापित किए जाएंगे, जिनमें 15 शहरी जंगल (नमो वन) और दक्षिण-पश्चिम दिल्ली में दो घने मियावाकी जंगल शामिल हैं। पौधारोपण कार्य अगले महीने शुरू होने की योजना है, जो मुख्यतः बंजर भूमि को हरित क्षेत्रों में बदल देगा। ये जंगल शहरी हरियाली बढ़ाएंगे, तापमान को नियंत्रित करेंगे, वायु गुणवत्ता में सुधार करेंगे और नागरिकों को अधिक मनोरंजन व विश्राम स्थल प्रदान करेंगे। प्रस्तावित स्थल रोहिणी, नरेला, अलीपुर, सातबाड़ी और मैदंगढ़ी में हैं, और प्रत्येक स्थल में जैव विविधता को बढ़ावा देने के लिए कम से कम दस पेड़ की प्रजातियाँ लगाई जाएंगी।

दो मियावाकी जंगल खरखरी जाटमल (6.02 एकड़) और जैनपुर (11.21 एकड़) में स्थापित होंगे, जिसमें उच्च घनत्व वाली स्थानीय पौधों की रोपाई की जाएगी ताकि तेजी से विकास और उच्च कार्बन अवशोषण सुनिश्चित किया जा सके, और ये कुछ वर्षों में परिपक्व हो जाएंगे। शहरी जंगलों में पारंपरिक दूरी के अनुसार पौधे लगाए जाएंगे, जिन्हें विकसित होने में चार से पांच वर्ष लगेंगे। पहल में स्थानीय प्रजातियों और स्तरित पारिस्थितिकी तंत्र पर जोर दिया गया है, जो दिल्ली को और अधिक हरित और स्वच्छ बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

## भारत तैयार कर रहा है 'व्हाइट रिवॉल्यूशन 2.0' के लिए, बढ़ाने के लिए डेयरी उत्पादकता और निर्यात



भारत दूसरे 'व्हाइट रिवॉल्यूशन' की दिशा में कदम बढ़ा रहा है, जिसमें डेयरी उत्पादकता, मूल्य संवर्धन और निर्यात क्षमता को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, ऐसा नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड (NDDB) के अध्यक्ष मीनश सी. शाह ने बताया।

केरल कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन (मिल्मा) और NDDB द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित राज्य स्तरीय सेमिनार में, श्री शाह ने कहा कि 'व्हाइट रिवॉल्यूशन 2.0' का उद्देश्य देश भर में डेयरी सहकारिताओं को मजबूत करना और अगले पांच वर्षों में दूध की खरीद को 10 करोड़ लीटर प्रति दिन से अधिक करना है।

उन्होंने जोर दिया कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए बेहतर प्रजनन, पशु स्वास्थ्य और पोषण कार्यक्रमों के माध्यम से उत्पादकता बढ़ाना अहम है। NDDB दूध मिलावट को रोकने और संगठित डेयरी क्षेत्र का हिस्सा 65% से बढ़ाकर 70% करने पर भी जोर दे रहा है।

सेमिनार में मूल्य संवर्धित उत्पादों के विकास और आने वाले दशकों में वैश्विक निर्यात बाजार में भारत के डेयरी क्षेत्र की हिस्सेदारी बढ़ाने की आवश्यकता पर भी चर्चा की गई।

## ₹947 करोड़ के डेयरी परियोजनाओं का उद्घाटन, भारत के आत्मनिर्भरता और ग्रामीण आजीविका को मजबूत करने के लिए



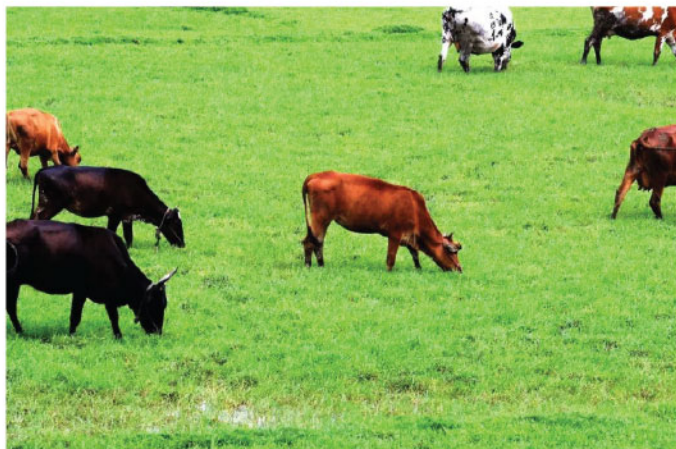
भारत के डेयरी और पशुपालन क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास की दिशा में कदम बढ़ाया गया है, जहाँ ₹947 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और ₹219 करोड़ की नई परियोजना का शिलान्यास किया गया। ये पहलें प्रधान मंत्री धन धान्य कृषि योजना (PM-DDKY) और मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस के तहत आत्मनिर्भरता और ग्रामीण समृद्धि को बढ़ावा देने वाले बड़े कृषि निवेश पैकेज का हिस्सा हैं।

उद्घाटित परियोजनाओं का उद्देश्य डेयरी और संबद्ध क्षेत्रों में उत्पादकता, पशु स्वास्थ्य और अवसंरचना को सशक्त बनाना है, साथ ही पशुपालन, मत्स्य पालन और मधुमक्खी पालन के

माध्यम से विविधीकरण को बढ़ावा देना है। इन पहलों में पशु रोगों की रोकथाम पर भी जोर दिया गया है, जिसमें 125 करोड़ से अधिक मुफ्त टीकाकरण का संचालन कर प्रमुख रोगों जैसे खुर-पाँव रोग को नियंत्रित किया गया।

ये प्रयास ग्रामीण भारत को आधुनिक, लचीला और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के व्यापक लक्ष्य से जुड़े हैं, जिससे किसानों और भूमि रहित परिवारों के लिए गैर-कृषि आय के स्रोत मजबूत हों और स्थायी अवसर उत्पन्न हों।

### NDDB और मदर डेयरी ने विदर्भ और मराठवाड़ा में डेयरी विकास परियोजना का दूसरा चरण शुरू किया



नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड (NDDB) और मदर डेयरी मिलकर विदर्भ और मराठवाड़ा के 19 जिलों में अपनी डेयरी विकास परियोजना का दूसरा चरण शुरू करने जा रहे हैं। इस पहल का उद्देश्य डेयरी मूल्य श्रृंखला को मजबूत करना, दूध संग्रह को बढ़ावा देना और बेहतर पशु उत्पादकता व चारे के प्रबंधन के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाना है।

किसानों को उच्च उत्पादन देने वाली गाय और भैंसों उपलब्ध कराई जाएंगी, साथ ही दूध की वसा और एसएनएफ (सॉलिड्स-नॉट-फैट) सामग्री बढ़ाने के लिए प्रजनन सप्लीमेंट और फ़ीड ऐडिटिव भी दिए जाएंगे। योजना में बहुवर्षीय चारे की खेती के लिए सब्सिडी, इलेक्ट्रिक चाफ़ कटर, सिलेज का

वितरण और आधुनिक डेयरी प्रबंधन प्रशिक्षण भी शामिल है।

यह परियोजना, स्व-रोज़गार और ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए संगठित दूध संग्रह और उत्पादन नेटवर्क के विस्तार के माध्यम से किसानों के लिए स्थायी आजीविका उत्पन्न करने और क्षेत्रीय आर्थिक चुनौतियों का समाधान करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

### ICAR-NDRI ने त्रिपुरा में किसानों के सशक्तिकरण के लिए पशु स्वास्थ्य और इनपुट वितरण शिविर आयोजित किया



ICAR-नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टिट्यूट (NDRI), ईस्टर्न रीजनल स्टेशन, कल्याणी, पश्चिम बंगाल ने NDRI-NEH परियोजना के तहत बगमा एग्री प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड (BAPCL), गोमती जिला, त्रिपुरा में एक दिवसीय पशु स्वास्थ्य और इनपुट वितरण शिविर आयोजित किया। इस पहल का उद्देश्य उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पशुपालन स्वास्थ्य, उत्पादकता और किसानों की आय को बढ़ावा देना था।

NDRI के प्रधान वैज्ञानिक डॉ. अशोक संत्रा ने जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों के बीच समग्र खेती (इंटीग्रेटेड फार्मिंग) के महत्व पर जोर दिया और कृषि एवं पशुपालन की आपसी निर्भरता के माध्यम से ग्रामीण आजीविका सशक्तिकरण पर

प्रकाश डाला।

कार्यक्रम में स्थानीय नेताओं, वरिष्ठ NDRI वैज्ञानिकों और गोमती, दक्षिण त्रिपुरा, खोवाई और सेपाहिजला जिलों के 120 से अधिक पशुपालक किसानों ने भाग लिया। किसानों को चिकेट्स, बतख के बच्चों, मिनरल मिक्सचर, फ़ीड और पशु चिकित्सकीय आपूर्ति प्रदान की गई।

डॉ. संत्रा ने उच्च लाभ के लिए वैज्ञानिक पशुपालन प्रथाओं को अपनाने का सुझाव दिया, जबकि BAPCL के प्रबंध निदेशक सुदीप मजूमदार ने NDRI के निरंतर सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का समापन रोग नियंत्रण और पशु पोषण पर इंटरैक्टिव सत्र के साथ हुआ।

## MeitY ने डेयरी, फसल गुणवत्ता और अपशिष्ट प्रबंधन के लिए AI और सेंसर आधारित समाधान लॉन्च किए



इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने AgriEnics कार्यक्रम के तहत डेयरी, फसल गुणवत्ता निगरानी और नगर निगम अपशिष्ट प्रबंधन को सुधारने के लिए उन्नत इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी-आधारित तकनीकें लॉन्च की हैं। इन तकनीकों को C-DAC कोलकाता ने IIT खड़गपुर, ICAR-NDRI कल्याणी, अकादमिक संस्थानों, अनुसंधान प्रयोगशालाओं और उद्योग भागीदारों के सहयोग से विकसित किया है।

डेयरी क्षेत्र में प्रमुख नवाचारों में M/s Handholders Global, भुवनेश्वर को हस्तांतरित किए गए गो-प (Go-P) नामक पहनने योग्य पशु स्वास्थ्य निगरानी सिस्टम और MAST-D, जो दूध में मैस्टिटिस का पता लगाता है, शामिल हैं। फसल गुणवत्ता के

लिए M/s Agnext Technologies, पंजाब को Grain-Ex (दाल की गुणवत्ता), CT-Vieu (सूखी लाल मिर्च) और RIGE-Sense (चावल की स्वचालित गुणवत्ता जांच) तकनीकें मिली हैं।

पर्यावरण निगरानी में, C-DAC कोलकाता ने नगर अपशिष्ट स्थलों के लिए पोर्टेबल सेंसर-आधारित गंध निगरानी उपकरण पेश किया, जो वास्तविक समय में उत्सर्जन की निगरानी कर कुशल अपशिष्ट प्रबंधन और सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा में मदद करता है।

## भारत बनने की राह पर विश्व का अन्न भंडार, नए कृषि कार्यक्रमों से उम्मीद



नई दिल्ली: भारत विश्व का अन्न भंडार बनने की दिशा में अग्रसर है। नए कार्यक्रम किसानों के कल्याण, खाद्य सुरक्षा और कृषि में आत्मनिर्भरता बढ़ाने पर केंद्रित हैं। रबी बोआई मौसम की शुरुआत के साथ, सरकार प्रमुख योजनाएँ लॉन्च करने जा रही है, जिनमें उत्पादन, उत्पादकता और फसल क्षेत्र विस्तार, विशेषकर दालों में वृद्धि शामिल है। 2014 के बाद खाद्य अनाज उत्पादन में 40% वृद्धि हुई है, गेहूँ और चावल में आत्मनिर्भरता हासिल की गई है, और निर्यात 4 करोड़ टन से अधिक हो गया है। दाल आत्मनिर्भरता मिशन के तहत 2030-31 तक खेती योग्य क्षेत्र 27.5 से 31 मिलियन हेक्टेयर तक बढ़ाने और उत्पादकता 880 किलो से 1,130 किलो प्रति

हेक्टेयर तक बढ़ाने का लक्ष्य है।

किसानों के समर्थन में 1,000 प्रसंस्करण इकाइयाँ स्थापित की जाएंगी और मिनी किट के माध्यम से प्रमाणित बीज वितरित किए जाएंगे। 100 कम उत्पादकता वाले जिलों में सिंचाई, भंडारण, ऋण सुविधा और फसल विविधीकरण में सुधार के लिए लक्षित उपाय किए जाएंगे। ये कार्यक्रम, मजबूत अनुसंधान और निगरानी तंत्र के साथ, राष्ट्रीय उत्पादन, किसानों की आय और दीर्घकालिक खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देंगे।

## सीईएसआई (CEASI) ने IDH Sutra 2025 प्रदर्शनी में डेयरी और कृषि पहले प्रदर्शित कीं

सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस फॉर एग्रीकल्चर स्किल्स इन इंडिया (CEASI) को आईडीएच सूत्रा 2025 प्रदर्शनी में भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ। यह एक प्रमुख आयोजन था जिसमें कृषि और डेयरी क्षेत्र से जुड़े नवाचारक, नीति निर्माता और संस्थान एक साथ आए। इस प्रदर्शनी में भाग लेकर सीईएसआई ने भारत की कृषि-खाद्य प्रणाली को और अधिक टिकाऊ और सशक्त बनाने के अपने संकल्प को दोहराया।

सीईएसआई के स्टॉल पर हमारे विभिन्न कार्यक्रमों और पहलों को प्रदर्शित किया गया, जो कृषि क्षेत्र में समग्र विकास को दर्शाते हैं। मुख्य रूप से चार विषयों पर ध्यान केंद्रित किया गया जलवायु सहनशील कृषि, सतत डेयरी विकास, कौशल विकास एवं किसान सशक्तिकरण, और कृषि-तकनीक एवं मशीनीकरण में नवाचार। प्रदर्शनी के दौरान विजिटर्स ने इंटरएक्टिव डिस्प्ले, वीडियो और चर्चाओं

के माध्यम से जाना कि सीईएसआई कैसे नई तकनीकों और प्रशिक्षण के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने और कृषि को टिकाऊ बनाने की दिशा में काम कर रहा है।

यह कार्यक्रम विचार-विमर्श और सहयोग के लिए एक महत्वपूर्ण मंच साबित हुआ, जहाँ सीईएसआई ने उद्योग विशेषज्ञों, सरकारी संस्थानों, विकास संगठनों और किसान समूहों के साथ संवाद किया। इन चर्चाओं से भविष्य में सहयोग और साझेदारी के नए अवसर खुले।

सीईएसआई आईडीएच सूत्रा 2025 के आयोजकों और सभी आगंतुकों का आभार व्यक्त करता है, जिन्होंने हमारे स्टॉल पर आकर हमारी पहल के बारे में जानकारी ली। आगे भी सीईएसआई किसानों के सशक्तिकरण, नवाचार को बढ़ावा देने और भारत की कृषि एवं डेयरी प्रणाली को टिकाऊ बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।



## सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस फॉर हॉर्टिकल्चर स्किल्स इन इंडिया एमआईडीएच के अंतर्गत 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन

सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस फॉर हॉर्टिकल्चर स्किल्स इन इंडिया (CEHSI) द्वारा मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ़ हॉर्टिकल्चर (MIDH) के तहत 3 दिवसीय फील्ड-आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित किए जा रहे हैं। यह पहल हरियाणा राज्य बागवानी विकास एजेंसी (HSHDA) के सहयोग से चलाई जा रही है। इसका उद्देश्य किसानों, ग्रामीण युवाओं और नए उद्यमियों को बागवानी क्षेत्र में व्यावहारिक कौशल और तकनीकी ज्ञान से सशक्त बनाना है। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में बागवानी से जुड़े कई रोजगार आधारित विषयों पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जैसे — सब्जी उत्पादक, जैविक उत्पादक, मशरूम उत्पादक, संरक्षित खेती उत्पादक, फसल कटाई के बाद हानि प्रबंधन तकनीशियन, मास्टर गार्डनर, मधुमक्खी पालक, उष्णकटिबंधीय एवं उप-उष्णकटिबंधीय फल उत्पादक और फ्लोरीकल्चरिस्ट (फूल उत्पादक) आदि। प्रत्येक प्रशिक्षण में कक्षा सत्रों के साथ-साथ खेतों पर व्यावहारिक प्रदर्शन भी शामिल है, ताकि प्रतिभागियों को व्यवहारिक अनुभव प्राप्त हो सके।

ये प्रशिक्षण कार्यक्रम हरियाणा के कई जिलों में आयोजित किए जा रहे हैं — झज्जर, कुरुक्षेत्र, करनाल और पंचकूला। प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम आधुनिक खेती की तकनीकों, संसाधनों के कुशल प्रबंधन, फसल कटाई के बाद के प्रबंधन और टिकाऊ खेती पद्धतियों पर केंद्रित है, जो एमआईडीएच के उद्देश्यों के अनुरूप है।

अब तक लगभग 160 प्रतिभागियों ने विभिन्न जिलों में इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया है। किसानों और ग्रामीण युवाओं से इस पहल को बहुत सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है। इन प्रशिक्षणों के माध्यम से स्थानीय क्षमता का निर्माण हो रहा है, रोजगार के नए अवसर बन रहे हैं और प्रतिभागी आधुनिक बागवानी तकनीकों से परिचित हो रहे हैं।

सीईएचएसआई (CEHSI) इन कार्यक्रमों के माध्यम से भारत के बागवानी क्षेत्र में कौशल विकास और नवाचार को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, जिससे कृषि प्रणाली अधिक उत्पादक, टिकाऊ और सशक्त बन सके।



## CEHSI द्वारा हिमाचल प्रदेश की महिला किसानों के लिए 5-दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण और एक्सपोज़र या

हॉर्टिकल्चर स्किल्स इन इंडिया (CEHSI), बागवानी विभाग हिमाचल प्रदेश के सहयोग से और मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर (MIDH) के अंतर्गत, हिमाचल प्रदेश की 31 महिला किसानों के लिए करनाल, हरियाणा में 5-दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण और एक्सपोज़र यात्रा आयोजित कर रहा है। यह कार्यक्रम वर्तमान में चल रहा है और इसमें प्रतिभागियों को कक्षा आधारित सत्रों और फील्ड डेमोंस्ट्रेशन के माध्यम से व्यावहारिक कौशल और तकनीकी ज्ञान प्रदान किया जा रहा है।

प्रशिक्षण में मुख्य विषय हैं फसल कटाई के बाद नुकसान प्रबंधन, अच्छी कृषि प्रथाएँ (GAPs) और क्लस्टर आधारित खेती। कक्षा सत्रों में गुणवत्ता प्रबंधन और मूल्य श्रृंखला के बारे में जानकारी दी जा रही है, जबकि फील्ड डेमोंस्ट्रेशन से किसान इन तकनीकों को सीधे अपने खेतों में लागू करना सीख रहे हैं।

कार्यक्रम के एक्सपोज़र भाग के तहत प्रतिभागी हरियाणा के प्रमुख बागवानी संस्थानों का दौरा कर रहे हैं, जैसे कि इंटीग्रेटेड बीकीपिंग डेवलपमेंट सेंटर (IBDC), रामनगर, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स (CEV), घरौंडा, सेंटर फॉर

सबट्रॉपिकल फ्रूट्स (CSTF), लदवा, महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी (MHU) और हॉर्टिकल्चर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (HTI)। इन दौरों में आधुनिक खेती तकनीकें, फसल कटाई के बाद प्रबंधन, कीट एवं परागक प्रबंधन और सफल क्लस्टर आधारित खेती के मॉडल दिखाए जा रहे हैं। कार्यक्रम प्रतिभागियों के बीच आपसी सीख, आत्मविश्वास और विशेषज्ञों के साथ सीधे संवाद को बढ़ावा देता है, जिससे वे अपने गाँवों की स्थानीय चुनौतियों का व्यावहारिक समाधान सीख सकें। शुरुआती प्रतिक्रिया में महिला किसान बहुत उत्साहित हैं और उन्होंने अपने गाँवों में सीखी गई तकनीकों को अपनाने की योजना बनाई है।

आवासीय प्रशिक्षण और एक्सपोज़र यात्रा के माध्यम से, CEHSI का उद्देश्य महिला किसानों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाना और बागवानी क्षेत्र में लैंगिक समानता और सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। यह पहल CEHSI की प्रतिबद्धता को दर्शाती है कि महिला किसान अधिक उत्पादक, सक्षम और टिकाऊ बागवानी भविष्य के लिए परिवर्तनकर्ता बन सकें।





# CEASI

CENTRES OF EXCELLENCE FOR  
AGRICULTURE SKILLS IN INDIA

---



(CEASI), Unit No. 101, First Floor, Greenwoods  
Plaza, Block 'B' Greenwoods City, Sector-45,  
Gurugram, Haryana-122009



+91 74287 06078



info@cedsi.in



www.ceasi.in



@ceasi\_india